

नरेंद्र मोदी के कार्यकाल (2014–2026) में भारत की विदेश नीति का पुनर्संरचनात्मक

विश्लेषण: बांग्लादेश के संदर्भ में उभरते एवं बदलते आयाम

Ms. Suman Yadav

Research Scholar

Deptt. of Sociology & political Science

Dayalbagh Educational Institute, Agra

Dr. Anju Sharma

Asstt. Prof.

Deptt. of Sociology & political Science

Dayalbagh Educational Institute, Agra

सार

इक्कीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में वैश्विक शक्ति-संतुलन, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक परस्पर-निर्भरता तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने भारत की विदेश नीति को नए सिरे से प्रभावित किया। वर्ष 2014 के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति ने पारंपरिक आदर्शवादी दृष्टिकोण के साथ-साथ व्यावहारिक यथार्थवाद, राष्ट्रीय हित, आर्थिक कूटनीति तथा क्षेत्रीय संपर्क को प्रमुख आधार बनाया। 'पड़ोसी प्रथम' (Neighbourhood First), 'एक्ट ईस्ट' (Act East) तथा SAGAR जैसी पहलों ने भारत की क्षेत्रीय रणनीति को नई दिशा प्रदान की, जिसका प्रभाव भारत-बांग्लादेश संबंधों में दिखाई देता है (Pant, 2022; Malone, 2014)।

भारत और बांग्लादेश के संबंध साझा इतिहास, सांस्कृतिक निकटता, आर्थिक परस्पर-निर्भरता तथा सुरक्षा हितों पर आधारित हैं। वर्ष 2015 का भूमि सीमा समझौता (Land Boundary Agreement) द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध हुई, जिसने दशकों पुराने सीमा विवाद का समाधान करने के साथ-साथ राजनीतिक विश्वास को सुदृढ़ किया (Ministry of External Affairs [MEA], 2015)। इसके साथ ही व्यापार, ऊर्जा सहयोग, संपर्क अवसंरचना, सीमा-पार विद्युत आपूर्ति, अंतर्देशीय जलमार्ग तथा बंदरगाह सहयोग ने दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई गहराई प्रदान की (World Bank, 2023)।

हालाँकि तीस्ता नदी जल-वितरण, व्यापार असंतुलन, अवैध प्रवासन, सीमा प्रबंधन, रोहिंग्या संकट तथा बांग्लादेश में चीन की बढ़ती आर्थिक एवं सामरिक उपस्थिति जैसी चुनौतियाँ भविष्य की द्विपक्षीय नीति को प्रभावित करती हैं। इसके बावजूद 2014–2026 की अवधि भारत-बांग्लादेश संबंधों के इतिहास में राजनीतिक विश्वास,

आर्थिक सहयोग तथा क्षेत्रीय रणनीतिक साझेदारी के महत्वपूर्ण चरणों में से एक मानी जा सकती है। प्रस्तुत अध्ययन इसी परिवर्तनशील प्रक्रिया का विश्लेषण करता है।

मुख्य शब्द: भारत की विदेश नीति, नरेंद्र मोदी, भारत-बांग्लादेश संबंध, पड़ोसी प्रथम नीति, एक्ट ईस्ट नीति, रणनीतिक साझेदारी, भूमि सीमा समझौता, हिंद-प्रशांत।

1. भारत की विदेश नीति: वैचारिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत की विदेश नीति का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, आर्थिक विकास तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ। प्रारंभिक वर्षों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता, पंचशील, उपनिवेशवाद-विरोध तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जैसे सिद्धांतों पर आधारित किया। इन सिद्धांतों ने भारत को नवस्वतंत्र देशों के मध्य नैतिक नेतृत्व प्रदान किया तथा एक स्वतंत्र विदेश नीति के विकास का आधार तैयार किया (Nehru, 1946/2004)।

1991 के आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारतीय विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिया। आर्थिक कूटनीति, विदेशी निवेश, ऊर्जा सुरक्षा तथा वैश्विक व्यापारिक सहभागिता विदेश नीति के प्रमुख आयाम बन गए। शीत युद्ध की समाप्ति और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय ने भारत को अधिक व्यावहारिक तथा राष्ट्रीय हित-आधारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया (Pant, 2022)।

वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति ने इसी विकासक्रम को अधिक सक्रिय स्वरूप प्रदान किया। विदेश नीति को घरेलू आर्थिक विकास, संपर्क अवसंरचना, ऊर्जा सुरक्षा, निवेश आकर्षण तथा क्षेत्रीय नेतृत्व से जोड़ा गया। इस अवधि में भारत ने 'पड़ोसी प्रथम', 'एक्ट ईस्ट' तथा SAGAR जैसी पहलों के माध्यम से दक्षिण एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने का प्रयास किया (Jaishankar, 2020)।

साथ ही, भारत ने बहु-संरेखण (Multi-alignment) की रणनीति अपनाते हुए अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया तथा खाड़ी देशों के साथ समानांतर संबंध विकसित किए। इस नीति का उद्देश्य किसी एक शक्ति-केंद्र पर निर्भर होने के बजाय राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संतुलित कूटनीतिक संबंध स्थापित करना था। इसके अतिरिक्त योग, प्रवासी भारतीय समुदाय, विकास सहयोग तथा मानवीय सहायता के माध्यम से भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को भी विदेश नीति के प्रभावी साधन के रूप में उपयोग किया (Nye, 2004)।

फिर भी भारतीय विदेश नीति अनेक समकालीन चुनौतियों का सामना कर रही है। दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, समुद्री सुरक्षा, साइबर खतरे तथा क्षेत्रीय राजनीतिक अस्थिरता ने विदेश नीति को अधिक जटिल बनाया है। ऐसे परिदृश्य में बांग्लादेश भारत की क्षेत्रीय रणनीति के अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभरा है। दोनों देशों के मध्य विकसित बहुआयामी सहयोग भारतीय विदेश नीति के व्यावहारिक एवं रणनीतिक स्वरूप का प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है।

1.1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने अधिक सक्रिय, व्यावहारिक एवं राष्ट्रीय हित-आधारित स्वरूप ग्रहण किया। यद्यपि भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत—रणनीतिक स्वायत्तता, संप्रभुता तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व—काफी हद तक यथावत रहे, किंतु उनके क्रियान्वयन में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई दिया। इस अवधि में विदेश नीति को केवल पारंपरिक कूटनीतिक संबंधों तक सीमित न रखकर आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक प्रतिष्ठा तथा सामरिक सहयोग के साथ जोड़ा गया (Jaishankar, 2020; Pant, 2022)।

मोदी सरकार की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं में व्यावहारिक यथार्थवाद (Pragmatic Realism) का महत्वपूर्ण स्थान रहा। विदेश नीति के निर्णयों में वैचारिक आग्रहों की अपेक्षा राष्ट्रीय हित, आर्थिक विकास और सामरिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई। परिणामस्वरूप व्यापार, निवेश, आपूर्ति श्रृंखलाएँ, प्रौद्योगिकी सहयोग तथा ऊर्जा सुरक्षा विदेश नीति के प्रमुख उपकरण बनकर उभरे। इस परिवर्तन ने भारतीय कूटनीति को अधिक परिणामोन्मुख तथा विकासोन्मुख बनाया।

इस अवधि की दूसरी प्रमुख विशेषता 'पड़ोसी प्रथम' (Neighbourhood First) नीति रही। दक्षिण एशिया को भारत की क्षेत्रीय रणनीति के केंद्र में रखते हुए पड़ोसी देशों के साथ विश्वास-निर्माण, विकास सहयोग, संपर्क अवसंरचना, ऊर्जा साझेदारी तथा सीमा प्रबंधन को प्राथमिकता प्रदान की गई। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव के साथ उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद और विकास परियोजनाओं का विस्तार इसी नीति के प्रमुख परिणामों में शामिल रहा।

इसके समानांतर 'एक्ट ईस्ट नीति' (Act East Policy) ने भारत की विदेश नीति को दक्षिण-पूर्व एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र तक विस्तारित किया। यह नीति पूर्ववर्ती Look East Policy की अपेक्षा अधिक व्यापक थी, जिसमें आर्थिक सहयोग के साथ-साथ सामरिक साझेदारी, समुद्री सुरक्षा तथा संपर्क अवसंरचना को भी महत्व

दिया गया। पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने में बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति ने उसे इस नीति का प्रमुख साझेदार बना दिया।

मोदी सरकार ने कनेक्टिविटी कूटनीति (Connectivity Diplomacy) को भी विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया। सड़क, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग, बंदरगाह, ऊर्जा गलियारे तथा डिजिटल संपर्क के विकास के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहित किया गया। विशेष रूप से भारत-बांग्लादेश संपर्क परियोजनाओं ने आर्थिक सहयोग को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विदेश नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम बहु-संरेखण (Multi-alignment) रहा। भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा खाड़ी देशों के साथ समानांतर रूप से सहयोग का विस्तार किया। इसका उद्देश्य किसी एक शक्ति-केंद्र पर निर्भर होने के बजाय विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संतुलित संबंध स्थापित करना था। साथ ही योग, प्रवासी भारतीय समुदाय, 'वैक्सीन मैत्री', विकास सहयोग तथा मानवीय सहायता के माध्यम से भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भी प्रभावी ढंग से उपयोग किया।

यद्यपि इस अवधि में भारतीय विदेश नीति ने अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त कीं, फिर भी चीन की बढ़ती क्षेत्रीय सक्रियता, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), सीमा सुरक्षा, हिंद-प्रशांत प्रतिस्पर्धा तथा पड़ोसी देशों की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ बनी रहीं। इन परिस्थितियों में भारत ने प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया, जिसमें बांग्लादेश भारत की क्षेत्रीय रणनीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा।

2. भारत-बांग्लादेश संबंधों का ऐतिहासिक विकास (1971-2014)

भारत-बांग्लादेश संबंध साझा इतिहास, सांस्कृतिक निकटता, भाषाई समानता तथा भौगोलिक परस्पर-निर्भरता पर आधारित हैं। लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी साझा सीमा, अंतरदेशीय नदियों का साझा तंत्र तथा ऐतिहासिक बंगाल की सांस्कृतिक विरासत इन संबंधों को दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में स्थान प्रदान करती है। इसलिए इन संबंधों का विकास केवल विदेश नीति का विषय नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक एकीकरण तथा भू-राजनीतिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों की वास्तविक आधारशिला 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान स्थापित हुई। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक असमानता तथा सैन्य दमन के परिणामस्वरूप उत्पन्न मानवीय संकट ने भारत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। लगभग एक करोड़ शरणार्थियों के भारत आगमन से उत्पन्न

परिस्थितियों में भारत ने कूटनीतिक, मानवीय तथा अंततः सैन्य सहयोग प्रदान किया। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की पराजय और 16 दिसंबर को बांग्लादेश की स्वतंत्रता ने दोनों देशों के मध्य दीर्घकालिक सहयोग की नींव रखी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने पुनर्निर्माण, मानवीय सहायता तथा अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1972-1975 का काल भारत-बांग्लादेश संबंधों का प्रारंभिक सहयोगात्मक चरण माना जाता है। इस अवधि में दोनों देशों ने मैत्री, सहयोग एवं शांति संधि पर हस्ताक्षर किए तथा संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers Commission) की स्थापना की। सीमा प्रबंधन, व्यापार, सांस्कृतिक सहयोग तथा नदी जल प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र विकसित किए गए। शेख मुजीबुर्रहमान और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच राजनीतिक विश्वास ने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष मजबूती प्रदान की।

किन्तु 1975 के बाद शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या और बांग्लादेश में सैन्य शासन की स्थापना ने दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया। सीमा विवाद, फरक्का बैराज, अवैध प्रवासन तथा जल-वितरण जैसे मुद्दे तनाव के प्रमुख कारण बने। यद्यपि संवाद जारी रहा, परंतु सहयोग की गति पहले की अपेक्षा धीमी पड़ गई।

1991 में लोकतांत्रिक शासन की पुनर्स्थापना और भारत में आर्थिक उदारीकरण ने संबंधों को नई दिशा प्रदान की। दोनों देशों ने व्यापार, सीमा प्रबंधन तथा क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी। वर्ष 1996 का गंगा जल बंटवारा समझौता विश्वास-निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हुआ। इसने यह प्रदर्शित किया कि जटिल सीमा-पार संसाधन संबंधी विवादों का समाधान संस्थागत संवाद के माध्यम से संभव है।

इसी अवधि में आर्थिक संबंधों का भी विस्तार हुआ। भारत से मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन तथा औद्योगिक कच्चे माल का निर्यात बढ़ा, जबकि बांग्लादेश से तैयार वस्त्र, जूट, चमड़ा तथा मत्स्य उत्पादों का आयात भी विस्तृत हुआ। यद्यपि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा, फिर भी दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग को दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया।

सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में निर्णायक परिवर्तन 2009 के बाद दिखाई दिया, जब शेख हसीना सरकार ने भारत-विरोधी उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। इससे आतंकवाद-रोधी सहयोग, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा सीमा प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हुआ और दोनों देशों के मध्य रणनीतिक विश्वास सुदृढ़ हुआ।

डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल (2004–2014) में भारत-बांग्लादेश संबंधों को नई संस्थागत दिशा मिली। सितंबर 2011 की ढाका यात्रा के दौरान सीमा निर्धारण, संपर्क अवसंरचना, ऊर्जा सहयोग तथा व्यापार से संबंधित अनेक समझौतों की आधारशिला रखी गई। यद्यपि भूमि सीमा समझौते का पूर्ण क्रियान्वयन बाद में वर्ष 2015 में हुआ, परंतु उसके लिए आवश्यक राजनीतिक एवं संवैधानिक सहमति के निर्माण की प्रक्रिया इसी काल में आगे बढ़ी। इस प्रकार वर्ष 2014 तक भारत-बांग्लादेश संबंध पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधों से आगे बढ़कर बहुआयामी रणनीतिक सहयोग की दिशा में अग्रसर हो चुके थे। यही आधार नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में संबंधों के तीव्र विस्तार का कारण बना।

3. भारत-बांग्लादेश संबंधों के उभरते एवं बदलते आयाम (2014–2026)

3.1 राजनीतिक एवं कूटनीतिक आयाम: विश्वास से रणनीतिक साझेदारी तक

वर्ष 2014 के पश्चात भारत-बांग्लादेश संबंधों ने एक नए चरण में प्रवेश किया, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग केवल पड़ोसी देशों के पारंपरिक संबंधों तक सीमित न रहकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की Neighbourhood First नीति तथा प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश की सहयोगात्मक विदेश नीति ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास को मजबूत किया। इस अवधि में नियमित उच्चस्तरीय वार्ताओं, द्विपक्षीय यात्राओं तथा बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय ने संबंधों को अधिक संस्थागत और स्थिर स्वरूप प्रदान किया।

इस राजनीतिक निकटता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में वर्ष 2015 का भूमि सीमा समझौता (Land Boundary Agreement—LBA) शामिल है। लगभग सात दशकों से लंबित सीमा संबंधी प्रश्नों के समाधान के रूप में इस समझौते के अंतर्गत 162 एन्क्लेवों का आदान-प्रदान किया गया तथा सीमावर्ती निवासियों को विधिक नागरिकता एवं प्रशासनिक पहचान प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी की गई। यह समझौता केवल सीमा निर्धारण का दस्तावेज नहीं था, बल्कि दक्षिण एशिया में शांतिपूर्ण विवाद-समाधान, राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा विश्वास-निर्माण का महत्वपूर्ण उदाहरण भी सिद्ध हुआ। इसने सीमा क्षेत्रों में प्रशासनिक स्पष्टता, विकास तथा सुरक्षा प्रबंधन को भी नई दिशा प्रदान की (MEA, 2015)।

इसी अवधि में दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र, BIMSTEC, IORA तथा अन्य क्षेत्रीय मंचों पर आतंकवाद-रोधी सहयोग, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास जैसे विषयों पर परस्पर सहयोग को सुदृढ़ किया। परिणामस्वरूप भारत-बांग्लादेश संबंध केवल द्विपक्षीय मुद्दों तक सीमित न रहकर क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग

के व्यापक ढाँचे का हिस्सा बन गए। बांग्लादेश भारत की Act East Policy तथा हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभरा, जिससे पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक एवं रणनीतिक महत्व में वृद्धि हुई।

हालाँकि इस अवधि में कुछ चुनौतियाँ भी बनी रहीं। तीस्ता नदी जल-वितरण समझौते का लंबित रहना, सीमा पर नागरिकों की मृत्यु से जुड़ी घटनाएँ, अवैध प्रवासन तथा बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन समय-समय पर द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करते रहे। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश में चीन की बढ़ती आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक उपस्थिति ने भारत के लिए नई भू-राजनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न कीं। इसके बावजूद भारत ने प्रतिस्पर्धा के स्थान पर विकास सहयोग, क्षमता निर्माण तथा संस्थागत संवाद को प्राथमिकता देते हुए संबंधों की निरंतरता बनाए रखने का प्रयास किया।

3.2 आर्थिक एवं व्यापारिक आयाम : आर्थिक कूटनीति से रणनीतिक साझेदारी तक

नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति को राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख साधनों में से एक के रूप में विकसित किया गया। बांग्लादेश इस नीति का महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर उभरा, जहाँ आर्थिक सहयोग को केवल व्यापार तक सीमित न रखकर निवेश, संपर्क अवसंरचना, ऊर्जा, औद्योगिक सहयोग तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण से जोड़ा गया। भारत ने बांग्लादेश को अपने पूर्वोत्तर राज्यों तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के मध्य एक संभावित आर्थिक सेतु के रूप में विकसित करने की रणनीति अपनाई।

वर्ष 2014 के पश्चात दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 2014-15 में लगभग 6-7 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार 2023-24 तक बढ़कर लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर से ऊपर पहुँच गया। भारत से पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, कपास, इस्पात तथा रसायनों का निर्यात बढ़ा, जबकि बांग्लादेश से तैयार वस्त्र, जूट उत्पाद, चमड़ा तथा मत्स्य उत्पादों का आयात भी विस्तृत हुआ। यह वृद्धि दोनों देशों की बढ़ती आर्थिक परस्पर-निर्भरता का संकेतक है।

यद्यपि व्यापार में उल्लेखनीय विस्तार हुआ, फिर भी व्यापार असंतुलन एक प्रमुख चुनौती बना रहा। भारत का निर्यात बांग्लादेश के निर्यात की तुलना में काफी अधिक है, जिससे व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में बना रहा। तथापि भारतीय निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बांग्लादेश के औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों के रूप में प्रयुक्त होता है, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं की पूरक प्रकृति स्पष्ट होती है।

दीर्घकालिक दृष्टि से भारत द्वारा बांग्लादेशी उत्पादों के लिए बाजार पहुँच का विस्तार तथा गैर-शुल्कीय बाधाओं में कमी इस असंतुलन को कम करने में सहायक हो सकती है।

आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण पक्ष भारत द्वारा प्रदान की गई ऋण सहायता (Line of Credit—LoC) तथा विकास साझेदारी रहा है। रेलवे, सड़क, पुल, बंदरगाह, विद्युत अवसंरचना तथा सीमा संपर्क जैसी परियोजनाओं में भारतीय सहायता ने बांग्लादेश के आर्थिक विकास और क्षेत्रीय संपर्क को नई गति प्रदान की। इसी प्रकार सीमा हाटों (Border Haats) ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय व्यापार, रोजगार तथा सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देकर आर्थिक कूटनीति का एक उपयोगी मॉडल प्रस्तुत किया।

समग्रतः 2014–2026 की अवधि में आर्थिक सहयोग भारत–बांग्लादेश संबंधों के सबसे गतिशील आयामों में से एक बनकर उभरा। आर्थिक कूटनीति ने न केवल द्विपक्षीय व्यापार को विस्तृत किया, बल्कि क्षेत्रीय रणनीतिक साझेदारी को भी सुदृढ़ किया। फिर भी व्यापार असंतुलन, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में परिवर्तन तथा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियाँ भविष्य में नीति-निर्माताओं के समक्ष महत्वपूर्ण बनी रहेंगी।

3.3 ऊर्जा कूटनीति एवं कनेक्टिविटी : क्षेत्रीय एकीकरण का नया आधार

वर्ष 2014 के पश्चात भारत–बांग्लादेश संबंधों में ऊर्जा सहयोग तथा संपर्क (Connectivity) सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाले क्षेत्रों में उभरे। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया कि दक्षिण एशिया में स्थायी आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण का आधार केवल राजनीतिक सहयोग नहीं, बल्कि मजबूत भौतिक एवं ऊर्जा अवसंरचना भी है। इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत दोनों देशों ने विद्युत व्यापार, सीमा-पार ऊर्जा ग्रिड, रेलवे, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग, बंदरगाह तथा डिजिटल संपर्क के क्षेत्रों में व्यापक सहयोग स्थापित किया। परिणामस्वरूप भारत–बांग्लादेश संबंध पारंपरिक द्विपक्षीय सहयोग से आगे बढ़कर क्षेत्रीय आर्थिक संपर्क के एक महत्वपूर्ण मॉडल के रूप में विकसित हुए।

ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ हुई। भारत से बांग्लादेश को विद्युत निर्यात में वृद्धि हुई तथा दोनों देशों ने सीमा-पार विद्युत ग्रिड और ऊर्जा अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग को संस्थागत रूप दिया। बहारामपुर–भेरामारा तथा त्रिपुरा–कोमिल्ला जैसी सीमा-पार विद्युत ग्रिड परियोजनाओं ने दोनों देशों के ऊर्जा सहयोग को मजबूत आधार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना (Rampal) तथा अन्य ऊर्जा निवेश परियोजनाओं ने ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा

दी। ऊर्जा सहयोग ने यह भी प्रदर्शित किया कि आर्थिक परस्पर-निर्भरता राजनीतिक विश्वास को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान कर सकती है।

कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रेलवे संपर्क का पुनर्जीवन भारत-बांग्लादेश संबंधों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा। स्वतंत्रता के बाद बंद हो चुके अनेक रेल मार्गों को पुनः सक्रिय किया गया। कोलकाता-ढाका मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता-खुलना बंधन एक्सप्रेस तथा अगरतला-अखौरा रेल संपर्क जैसी परियोजनाओं ने लोगों, व्यापार तथा पर्यटन के आवागमन को सरल बनाया। इसी प्रकार सड़क संपर्क तथा एकीकृत चेक पोस्ट (Integrated Check Posts) के विकास ने सीमा-पार व्यापार की लागत और समय को कम करने में योगदान दिया।

अंतर्देशीय जलमार्ग सहयोग भी इस अवधि की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा। गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी प्रणाली के माध्यम से दोनों देशों ने माल परिवहन को अधिक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल बनाने का प्रयास किया। Protocol on Inland Water Transit and Trade (PIWTT) के अंतर्गत जलमार्गों के उपयोग का विस्तार हुआ, जिससे विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिवहन लागत में कमी लाने की संभावनाएँ बढ़ीं। इसके अतिरिक्त भारत को चटगाँव एवं मोंगला बंदरगाहों के उपयोग की अनुमति मिलने से क्षेत्रीय संपर्क को नई गति मिली तथा पूर्वोत्तर भारत की समुद्री पहुँच अधिक प्रभावी हुई।

डिजिटल एवं आर्थिक संपर्क के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने सीमा-पार व्यापार प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, सीमा शुल्क सहयोग, ई-गवर्नेंस तथा वित्तीय संपर्क को प्रोत्साहित किया। इन पहलों ने न केवल व्यापारिक दक्षता में वृद्धि की, बल्कि क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को भी मजबूत करने में योगदान दिया। वस्तुतः ऊर्जा एवं संपर्क सहयोग ने भारत-बांग्लादेश संबंधों को केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित न रखकर दक्षिण एशिया में व्यापक आर्थिक एकीकरण की संभावनाओं को मजबूत किया।

3.4 सुरक्षा एवं सामरिक सहयोग

भारत और बांग्लादेश के मध्य सुरक्षा सहयोग वर्ष 2014 के पश्चात द्विपक्षीय संबंधों का एक संवेदनशील तथा रणनीतिक आयाम बनकर उभरा। लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी साझा सीमा, सीमा-पार अपराध, आतंकवाद, उग्रवाद, मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी तथा अवैध प्रवासन जैसी चुनौतियों ने दोनों देशों को सुरक्षा सहयोग के लिए अधिक संस्थागत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने सुरक्षा सहयोग को Neighbourhood First नीति का महत्वपूर्ण अंग बनाया, जबकि बांग्लादेश ने भी भारत-विरोधी उग्रवादी गतिविधियों के प्रति कठोर रुख अपनाया।

आतंकवाद-रोधी सहयोग इस अवधि की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक रहा। दोनों देशों के मध्य खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, सीमा-पार आतंकवादी नेटवर्क पर कार्रवाई तथा उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध प्रयासों ने पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा स्थिति को अधिक स्थिर बनाने में योगदान दिया। बांग्लादेश सरकार द्वारा भारत-विरोधी उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य रणनीतिक विश्वास को और सुदृढ़ किया।

सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के सीमा सुरक्षा बल (BSF) तथा बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड (BGB) के मध्य नियमित समन्वय बैठकों, संयुक्त गश्त तथा समन्वित सीमा प्रबंधन के माध्यम से सीमा-पार अपराधों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। यद्यपि समय-समय पर सीमा पर नागरिकों की मृत्यु तथा तस्करी से संबंधित घटनाएँ सामने आती रहीं, फिर भी संवाद की निरंतरता ने इन मुद्दों को व्यापक राजनीतिक विवाद बनने से काफी हद तक रोके रखा।

हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा भी द्विपक्षीय सहयोग का एक नया क्षेत्र बनकर उभरी। समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा, मानवीय सहायता एवं आपदा प्रबंधन तथा समुद्री संसाधनों के संरक्षण में सहयोग ने दोनों देशों की सामरिक साझेदारी को विस्तृत किया। भारत की SAGAR (Security and Growth for All in the Region) पहल के संदर्भ में बांग्लादेश की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही।

हालाँकि सुरक्षा सहयोग के समक्ष कुछ चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। रोहिंग्या शरणार्थी संकट, सीमा-पार अवैध प्रवासन, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सामरिक उपस्थिति भविष्य में भारत-बांग्लादेश सुरक्षा सहयोग की दिशा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आवश्यक है कि दोनों देश संस्थागत सुरक्षा तंत्र, समुद्री सहयोग तथा सीमा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाकर क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ करें।

4. चुनौतियाँ एवं भविष्य की संभावनाएँ

यद्यपि 2014-2026 के दौरान भारत-बांग्लादेश संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, तथापि कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। इनमें तीस्ता नदी जल-वितरण समझौते का लंबित रहना, व्यापार असंतुलन, सीमा-पार अवैध गतिविधियाँ, अवैध प्रवासन, रोहिंग्या संकट तथा बांग्लादेश में चीन की बढ़ती आर्थिक एवं रणनीतिक उपस्थिति प्रमुख हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति पर्याप्त नहीं

होगी, बल्कि दीर्घकालिक संस्थागत सहयोग, पारदर्शी संवाद तथा परस्पर विश्वास की निरंतरता भी आवश्यक होगी।

भविष्य की दृष्टि से भारत-बांग्लादेश संबंधों की संभावनाएँ व्यापक हैं। ऊर्जा व्यापार, हरित प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं तथा बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय के माध्यम से दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को और अधिक गहरा कर सकते हैं। विशेष रूप से भारत की Act East Policy तथा हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण की सफलता काफी हद तक बांग्लादेश के साथ स्थायी, संतुलित और विश्वासपूर्ण संबंधों पर निर्भर करेगी।

भविष्य में दोनों देशों के लिए यह भी आवश्यक होगा कि द्विपक्षीय संबंधों को केवल सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण से न देखा जाए, बल्कि जल संसाधन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, सीमा क्षेत्रों का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी तथा जन-से-जन संपर्क जैसे क्षेत्रों को भी रणनीतिक साझेदारी का अभिन्न अंग बनाया जाए। इससे द्विपक्षीय संबंधों की सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूमि और अधिक मजबूत हो सकती है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्ष 2014-2026 भारत-बांग्लादेश संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी चरण रहा है। इस अवधि में दोनों देशों के संबंध पारंपरिक पड़ोसी सहयोग से आगे बढ़कर व्यापक एवं बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी की दिशा में विकसित हुए। भूमि सीमा समझौता, बढ़ता व्यापार, ऊर्जा सहयोग, संपर्क परियोजनाएँ, सुरक्षा समन्वय तथा क्षेत्रीय कूटनीति इस परिवर्तन के प्रमुख आधार रहे।

यद्यपि कुछ जटिल द्विपक्षीय प्रश्न अभी भी अनसुलझे हैं, फिर भी समग्र रूप से इस अवधि ने भारत-बांग्लादेश संबंधों को अधिक संस्थागत, परस्पर-निर्भर तथा रणनीतिक स्वरूप प्रदान किया। भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति और बांग्लादेश के साथ विकसित सहयोग ने यह प्रदर्शित किया है कि साझा हितों, आर्थिक परस्पर-निर्भरता तथा संस्थागत संवाद के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपेक्षाकृत स्थिर और परिणामोन्मुख द्विपक्षीय संबंध विकसित किए जा सकते हैं।

यदि दोनों देश पारस्परिक सम्मान, समानता, विकास साझेदारी तथा संस्थागत सहयोग की दिशा को बनाए रखते हैं, तो भारत-बांग्लादेश संबंध भविष्य में दक्षिण एशिया की स्थिरता, आर्थिक समृद्धि तथा क्षेत्रीय एकीकरण के महत्वपूर्ण मॉडलों में से एक के रूप में स्थापित हो सकते हैं। तथापि इस साझेदारी की दीर्घकालिक

सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश तीस्ता जल-विवाद, सीमा-संबंधी संवेदनशीलताओं, व्यापार असंतुलन, प्रवासन तथा बदलती क्षेत्रीय भू-राजनीति जैसी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार करते हैं।

सन्दर्भ सूची

- Bammi, Y. M. (2010). *India-Bangladesh relations: The way ahead*. Vij Books India.
- Chakravarty, P. R. (2025). *Transformation: Emergence of Bangladesh and evolution of India-Bangladesh ties*. Routledge.
- Gupta, A., Kumar, A., Pattanaik, S. S., Datta, S., & Behuria, A. K. (2011). *India-Bangladesh relations: Towards convergence*. Institute for Defence Studies and Analyses.
- Islam, M. S. (2021). *Fifty years of Bangladesh-India relations: Issues, challenges and possibilities*. Pentagon Press.
- Jaishankar, S. (2020). *The India way: Strategies for an uncertain world*. HarperCollins Publishers India.
- Kashyap, S. G. (2022). *India-Bangladesh: Fifty years of friendship*. Pentagon Press.
- Ministry of External Affairs, Government of India. (2015). *Land boundary agreement between India and Bangladesh*. Government of India.
- Ministry of External Affairs, Government of India. (2024). *Brief on India-Bangladesh bilateral relations*. Government of India.
- Pant, H. V. (Ed.). (2009). *Indian foreign policy in a unipolar world*. Routledge.
- Pant, H. V. (Ed.). (2022). *India and global governance: A rising power and its discontents*. Routledge.
- Riaz, A. (2016). *Bangladesh: A political history since independence*. I.B. Tauris.
- World Bank. (2021). *Connecting to thrive: Challenges and opportunities of transport integration in Eastern South Asia*. World Bank.